(b) if so, what is the quantity of each imported during the last two years, yearwise;

(c) what are the names of the companies which imported the above drugs and what are the names of the countries from which these were imported;

(d) whether it is a fact that these drugs are produced in the country from basic stage;

(e) whether it is also a fact that production of these drugs are much higher than the total requirement of the country;

(f) whether it is a fact that Government have received a proposal to ban the imports of these drugs?

(g) if so, what are the details thereof and by when ban will be imposed on the imports of these drugs?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) to (c) Import of individual drugs is not being monitored by this Department.

(d) The stages of manufacture allowed for these drugs are given below:—

Metoprolol Tartarate—4 methoxy Ethyl Phenol

Albendazole—Meta-chloroaniline

Alprazolam—4-chloroquin

Fenbendazole—2-nitro-5-chloro aniline

(e) This Department monitors production of only some important bulk drugs and formulations.

(f) to (g) Representations have been received for shifting of one item namely, Albendazole from OGL to 3(a) of the EXIM Policy. The same has been examined and action taken, taking into consideration various factors such as demand, production, number of manufacturers, availability etc.

टिहरी बांध परियोजना की लागत

1521. श्री राम जेठमलानी: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिहरी बांध के निर्माण के लिये सरकार की वर्तमान निर्धारित लागत कितनी है ;

(ख) इस लागत के लिये क्या संसाधन तथा व्यवस्थाएं हैं ; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने के लिये कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा मंत्री, साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) टिहरी बांध परियोजना (टिहरी कामप्लैक्स का चरण-I) की अनुमानित लागत 1474 करोड़ रुपये है जबकि सम्पूर्ण टिहरी जल विद्युत कामप्लेक्स की लागत 3006.12 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) परियोजना भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में क्रियान्वित की जा रही है । परियोजना के वित्तपोषण के लिये इक्विटी वित्तीय भागीदारी क्रमशः 75:25 के अनुपात में है । किसी कमी की सम्पूर्ण लागत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जायेगी । प्रस्तावित सघ टिहरी जल विद्युत कामप्लेक्स के लिये 1000 मिलियन रुपये की तकनीकी और वित्तीय व्यवस्था देने के लिये सहमत हो गया है ।

(ग) टिहरी बांध चरण-I परियोजना के जून 1997 तक पूरी किये जाने की प्रत्याशा है ।

पंजाब में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना

1522. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ उद्योगों की स्थापना की गई है ;